TITLE CODE : UPHIN51496
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 212
दि. 03.12.2025,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : VINOD KUMARI   Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

काशी एवं तमिलनाडु की महान विभूतियों के जीवन दर्शन तथा केंद्र सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए किये जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन

वाराणसी के नमो घाट पर आज से शुरू हुए 'काशी तमिल संगमम् 4.0' में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की इकाई केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा काशी एवं तमिलनाडु की महान विभूतियों के जीवन दर्शन तथा केंद्र सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए किये जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमिलनाडु के राज्यपाल आर. एन. रवि, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पुडुचेरी के उपराज्यपाल के. कैलाश नाथन समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने प्रदर्शनी का किया अवलोकन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा आयोजित प्रदर्शनी को सराहा कहा इससे आम लोग काशी एवं तमिल की संस्कृतियों के साथ-साथ सरकार द्वारा जन कल्याण हेतु किये जा रहे प्रयासों से होंगे अवगत

(जीएनएस)।

वाराणसी के नमो घाट पर आज से शुरू हुए 'काशी तमिल संगमम् 4.0' में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की इकाई केंद्रीय संचार ब्यूरो, लखनऊ द्वारा काशी एवं तमिलनाडु की महान विभूतियों के जीवन दर्शन तथा केंद्र सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए किये जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय मामलों के राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का आज उद्घाटन किया। इसके उपरांत प्रदर्शनी को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। यह प्रदर्शनी 15 दिसंबर तक निरंतर रहेगी।

प्रदर्शनी के पहले दिन आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमिलनाडु के राज्यपाल आर. एन. रवि, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पुडुचेरी के उपराज्यपाल के. कैलाशनाथन, उत्तर प्रदेश के

उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक समेत अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा आयोजित प्रदर्शनी को सराहा। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा इससे आम लोग काशी एवं तमिल की संस्कृतियों के साथ - साथ सरकार द्वारा जन कल्याण हेतु किये जा रहे प्रयासों से अवगत होंगे।

तमिलनाडु से आये हुए पत्रकार दल तथा काशी तमिल संगमम् की कवरेज कर रहे पत्रकारों तथा बड़ी संख्या में आम लोगों द्वारा भी प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया।

काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने वाले 'काशी तमिल संगमम्' के इस चतुर्थ संस्करण में केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा लगायी गयी चित्र प्रदर्शनी में तमिलनाडु एवं काशी की महान विभूतियों के राष्ट्र निर्माण में योगदान एवं उनकी उपलब्धियां को दशार्या गया है। चित्र प्रदर्शनी में तमिलनाडु की महान विभूतियों जैसे ऋषि अगस्त्य, तमिल महिला कवि संत अव्वैयार, तमिल कवि संत तिरुवल्लुवर, कवयित्री और संत कारैकल अम्माइयार, भक्ति आंदोलन की कवि एवं संत अंडाल (कोधाई), थिरूनावुक्कारसर, तमिल कवि और समाज सुधारक श्री रामलिंग स्वामी (वल्लालर), तमिल विद्वान यू. वी. स्वामीनाथ अय्यर, अग्रणी समाज सुधारक, चिकित्सक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ब्रिटिश भारत में पहली महिला विधायक डॉ. मुथुलक्ष्मी रेड्डी, गणितज्ञ श्री निवास रामानुजन, अविष्कारक और उद्योगपति जी.डी. नायडू, खगोलशास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन, भारत के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम, नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकटरामन रामकृष्णन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नोबेल पुरस्कार विजेता एवं महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सुप्रसिद्ध राजनेता एवं भारत रत्न के. कामराज, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं सुप्रसिद्ध राजनेता चिदंबरम सुब्रमण्यम, महान अभिनेता एवं राजनेता एम. जी. रामचंद्रन इत्यादि के जीवन दर्शन को चित्रों एवं शब्दों में दशार्या गया है।

इसी प्रकार काशी की महान विभूतियां जैसे संत कबीरदास, संत रविदास, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शिक्षाविद पंडित मदन मोहन मालवीय, सुप्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, विश्व प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार पंडित रविशंकर, महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद इत्यादि के जीवन दर्शन को चित्रों शब्दों के माध्यम से दशार्या गया है।

चित्र प्रदर्शनी में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में किये जा रहे सरकार के जन कल्याणकारी नीतियों, प्रयासों एवं योजनाओं को भी दशार्या गया है। जिसमें केंद्र सरकार द्वारा हाल में श्रम सुधार के लिए बनाये गये कानूनों, विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं पर जीएसटी के दरों को कम करने के लिये किए गये प्रयासों की जानकारी दर्शकों और जनसामान्य के लिए प्रदर्शित की गई है।

पीएम मोदी से किस एजेंडे पर होगी बात, भारत आने से पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बताया, यूरोप पर क्यों बरसे?

(जीएनएस)।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरे से पहले बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि वो पीएम मोदी संग मुलाकात के दौरान किन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। साथ ही इस दौरान रूसी राष्ट्रपति यूरोप पर जमकर बरसते भी नजर आए।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। वो 4 और 5 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में रहेंगे। रूसी राष्ट्रपति के इस दौरे पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। इस यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच कई अहम समझौते कर सकते हैं। इस यात्रा से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग मुलाकात पर बयान सामने आया है। इस दौरान वो अमेरिका और यूरोप पर बरसते नजर आए।

व्लादिमीर पुतिन दिल्ली में 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दिल्ली आने से पहले पुतिन ने यूरोप को सीधा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर यूरोप किसी भी तरह का संघर्ष या जंग चाहता है, तो

इसके लिए रूस पूरी तरह तैयार है।

भारत दौरे से पहले आया पुतिन का बयान

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वीटीबी के कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी और प्रधानमंत्री की आगामी भारत यात्रा के दौरान मुलाकात होने वाली है। इस दौरान वे भारत संग व्यापार और आयात को लेकर विस्तृत चर्चा करेंगे। पुतिन ने आगे ये भी कहा कि रूस 'स्वतंत्र आर्थिक नीति' पर काम जारी रहे और सिर्फ अपने देश के हित को ध्यान में रखेगा। उन्होंने भारत और चीन का जिक्र कर कहा कि पिछले तीन सालों में दोनों देशों के साथ रूस का व्यापार काफी बढ़ा है।

यूरोपीय देशों की शांति की कोई योजना नहीं- पुतिन

रूसी राष्ट्रपति ने बरसते हुए कहा कि यूरोपीय देशों की शांति की कोई योजना नहीं है। वो युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर यूरोप युद्ध लड़ना चाहता है, तो हम तैयार हैं।

प्रधानमंत्री ने असम दिवस पर असम के लोगों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने असम दिवस पर असम के बहनों और भाइयों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि आज स्वर्गदेव चाओलुंग सुकाफा के विजन को पूरा करने के हमारे संकल्प को दोहराने का अवसर है।

श्री मोदी ने यह भी कहा, "पिछले कुछ सालों में, केंद्र और असम में एनडीए सरकारें असम की तरक्की को बढ़ावा देने के लिए निरंतर काम कर रही हैं।

फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में काफी तरक्की हुई है। ताई-अहोम कल्चर और ताई भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इससे असम के युवाओं को बहुत लाभ होगा।" प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया "असम के मेरे बहनों और भाइयों को असम दिवस पर शुभकामनाएं।

संचार साथी ऐप के अफवाहों पर केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पष्टीकरण दिया, ऐप स्वैच्छिक पंजीकरण के बाद ही सक्रिय होता है

उपयोगकर्ता किसी भी समय ऐप हटा सकते हैं: श्री सिंधिया

संचार साथी निगरानी नहीं है, यह जनभागीदारी पर आधारित एक नागरिक सुरक्षा उपकरण है

(जीएनएस)।

केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार साथी ऐप के नियमों को स्पष्ट करते हुए कहा कि संचार साथी, पूरी तरह से लोकतांत्रिक और स्वैच्छिक है। उपयोगकर्ता अपनी सुविधानुसार इसके लाभों को उठाने के लिए ऐप को सक्रिय कर सकते हैं, और वे इसे किसी भी समय अपने डिवाइस से डिलीट कर सकते हैं।

नागरिक-प्रथम और पूर्णतः प्राइवेसी-सेफ प्लेटफॉर्म

केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। संचार साथी उसी दिशा में एक मजबूत कदम है, जो हर मोबाइल यूजर को सशक्त, सुरक्षित और जागरूक बनाता है। यह निगरानी का माध्यम नहीं, बल्कि जनभागीदारी पर आधारित एक पारदर्शी

डिजिटल सुरक्षा प्लेटफॉर्म है। उन्होंने बताया कि यह ऐप और पोर्टल नागरिकों को अपने मोबाइल नंबर की सुरक्षा, फर्जी कनेक्शनों की पहचान, खोए-चोरी हुए फोन की ट्रैकिंग और साइबर ठगी से बचाव जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में सक्षम बनाता है। संचार साथी का प्रभाव और मापनीय परिणाम, अपने शुभारंभ के बाद से, संचार साथी ने अच्छे परिणाम दिए हैं: 21.5 करोड़ से अधिक पोर्टल विज़िट, 1.4 करोड़ से अधिक ऐप डाउनलोड, नागरिकों द्वारा "नॉट माई नंबर" चुनने से 1.43 करोड़ से अधिक मोबाइल कनेक्शन काट दिए गए, 26 लाख खोए/चोरी हुए मोबाइल फोन का पता लगाया गया, जिनमें से 7.23 लाख सफलतापूर्वक वापस किए गए, नागरिक रिपोर्टों के आधार पर 40.96 लाख धोखाधड़ी वाले कनेक्शन काटे गए, धोखाधड़ी से जुड़े 6.2 लाख आईएमईआई ब्लॉक किए गए, वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (एफआरआई) के माध्यम से 475 करोड़ रुपये के संभावित वित्तीय नुकसान को रोका गया।

साइबर सुरक्षा ही है सुरक्षा संचार साथी का मूल लक्ष्य

केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने बताया कि ऐप के कॉल लॉग फीचर के माध्यम से किसी भी संदिग्ध नंबर की शिकायत दर्ज की जा सकती है, जिससे नागरिक स्वयं और दूसरों को संभावित धोखाधड़ी से बचा सकते हैं। सिंधिया ने कहा कि डिजिटल सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

भारत-मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एकुवेरिन केरल में शुरू हुआ

भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (एमएनडीएफ) के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एकुवेरिन का 14वां संस्करण आज केरल के तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास 2 से 15

दिसंबर, 2025 तक चलेगा। गढ़वाल राइफल्स की एक बटालियन द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए 45 कर्मियों वाली भारतीय सेना की टुकड़ी, मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए समान क्षमता वाले मालदीव के एक दल के साथ भाग ले रही है।

धिवेही में "एकुवेरिन" का अर्थ "मित्र" होता है, जो दोनों देशों के बीच मित्रता, आपसी विश्वास और सैन्य सहयोग के गहरे बंधनों को दशार्ता है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने लड़ाकू विमानों के लिए विकसित उन्नत एस्केप सिस्टम का उच्च गति पर रॉकेट-स्लेज परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया

(जीएनएस)।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने लड़ाकू विमानों से बाहर निकलने के लिए विकसित एस्केप सिस्टम का नियंत्रित वेग पर उच्च-गति रॉकेट-स्लेज परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी की रेल-ट्रैक रॉकेट-स्लेज सुविधा में किए गए इस परीक्षण में कैनोपी सेवरेंस, इजेक्शन सीक्वेंसिंग और संपूर्ण एयरक्रू रिकवरी प्रक्रिया की प्रभावी पुष्टि देखी गई।

यह परीक्षण एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (एडीए) और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के सहयोग से सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया। यह अत्यंत जटिल और गतिशील परीक्षण भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल करता है, जिनके पास उन्नत इन-हाउस एस्केप सिस्टम के पूर्ण परीक्षण की क्षमता उपलब्ध है।

गतिशील इजेक्शन परीक्षण, नेट टेस्ट या जीरो-जीरो टेस्ट जैसे स्थैतिक परीक्षणों की तुलना में कहीं अधिक जटिल होते हैं और इजेक्शन सीट के समग्र प्रदर्शन तथा कैनोपी सेवरेंस सिस्टम की वास्तविक प्रभावकारिता का सबसे विश्वसनीय मानक माने जाते हैं। इस परीक्षण के दौरान एलसीए विमान के अग्रभाग को एक दोहरी स्लेज प्रणाली के साथ संयोजित किया गया, जिसे कई ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर्स के चरणबद्ध प्रज्वलन द्वारा नियंत्रित वेग पर सटीक रूप से आगे बढ़ाया गया।

कैनोपी फ्रेजिलाइजेशन पैटर्न, इजेक्शन सीक्वेंसिंग और संपूर्ण एयरक्रू रिकवरी प्रक्रिया का मूल्यांकन एक इंस्ट्रूमेंटेड एंथ्रोपोमॉर्फिक टेस्ट डमी के माध्यम से किया गया, जिसने इजेक्टेड पायलट द्वारा वास्तविक परिस्थितियों में अनुभव किए जाने वाले महत्त्वपूर्ण भार, क्षण तथा त्वरण को सटीक रूप से रिकॉर्ड किया। पूरे परीक्षण अनुक्रम को ऑनबोर्ड और ग्राउंड-आधारित हाई-स्पीड इमेजिंग सिस्टम की मदद से विस्तृत रूप में कैप्चर किया गया।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने शीतकालीन मौसम में इन्फ्लूएंजा फैलने से रोकने की तैयारियों की समीक्षा की

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय देश में मौसमी इन्फ्लूएंजा सहित श्वसन संबंधी बीमारियों की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है

भारत श्वसन संबंधी बीमारियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है, निगरानी में कोई असामान्य वृद्धि नहीं दिखी

(जीएनएस)।

सर्दियों में फैलने वाले इन्फ्लूएंजा को रोकने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लेने के लिए , केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय

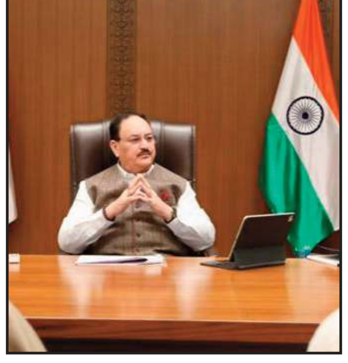

की स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) डॉ. सुनीता शर्मा, संयुक्त सचिव (लोक स्वास्थ्य) श्रीमती वंदना जैन, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) के निदेशक प्रो. (डॉ.) रंजन दास और आपदा प्रबंधन (डीएम) प्रकोष्ठ तथा एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) के विशेषज्ञों ने भाग लिया।

कर्तव्य भवन 1 में बैठक के दौरान, सचिव (स्वास्थ्य) ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को बताया कि भारत में आमतौर पर इन्फ्लूएंजा के दो मौसमी चरम अनुभव होते हैं - अगस्त-अक्टूबर (मानसून चरम) और जनवरी-मार्च (शीतकालीन चरम)।

वर्ष 2014-15 के दौरान मौसमी इन्फ्लूएंजा के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि को याद करते हुए, श्री नड्डा ने वर्तमान स्थिति पर अद्यतन जानकारी मांगी तथा पूछा कि क्या वर्तमान में प्रचलित वायरस के प्रकारों में ऐतिहासिक रुझानों से कोई भिन्नता है।

पीएम ई-ड्राइव योजना

पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत 23.11.2025 तक 1634.62 करोड़ रुपए की सबसिडी वितरित की गई।

पीएम ई-ड्राइव योजना के अधीन ई-एंबुलेंस के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ई-एंबुलेंस के लिए दिशानिर्देशों को अधिसूचित करने

के उद्देश्य से हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया गया है। योजना को अन्य श्रेणियों समेत ई-एंबुलेंस के लिए 31.03.2028 तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन ई-दोपहिया और ई-तिपहिया के लिए समय सीमा 31.03. 2026 तक ही होगी।

पश्चिम रेलवे द्वारा महापरिनिर्वाण दिवस पर दादर स्टेशन पर सुरक्षा एवं सुविधा की व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित

मुंबई, पश्चिम रेलवे ने भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर 6 दिसंबर, 2025 को दादर स्टेशन पर बड़ी संख्या में आने वाले अनुयायियों की सुरक्षा, सुविधा और भीड़ प्रबंधन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। लगभग 700 जीआरपी और आरपीएफ कर्मियों को दादर स्टेशन के प्लेटफॉर्म, पुलों, प्रवेशझनिकास द्वारों और रेलवे परिसर में चौबीसों घंटे तैनात किया जाएगा। स्टेशन पर 160 सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है और सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष की 24ग्7 निगरानी के लिए स्टाफ तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा को उन्नत वीडियो एनालिटिक्स सुविधाओं जैसे फेस रिकग्निशन सिस्टम, पीपल डेंसिटी एनालिसिस, लेफ्ट-ओवर लगेज डिटेक्शन और लाइन-क्रॉसिंग अलर्ट आदि की सहायता से और मजबूत किया जा रहा है।

पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दादर स्टेशन पर आगंतुकों और चैत्यभूमि जाने वाले अनुयायियों की सहायता के लिए 24ग्7 कार्यरत कई हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। इन हेल्प डेस्क पर तैनात आरपीएफ, जीआरपी और टिकट जांच कर्मचारी आगंतुकों को चैत्यभूमि, राजगृह, ट्रेन समय और अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त, आधुनिक उपकरणों का उपयोग करते हुए आरपीएफ डॉग स्क्वॉड, क्विक रिस्पॉन्स टीम और जीआरपी बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड (इऊऊर) द्वारा लगातार एंटी-सैबोटाज जांच की जाएगी। भीड़ प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम रेलवे ने बीएमसी एफओबी और तिलक एफओबी जैसे भीड़-प्रवण क्षेत्रों में बैरिकेडिंग और रस्सियों के माध्यम से सेगरेगेशन की व्यवस्था की है। प्रवेश और निकास बिंदुओं पर नियंत्रित डायवर्जन की भी व्यवस्था की गई है। सुगम आवागमन के लिए सभी पुलों और द्वारों पर स्पष्ट दिशा-सूचक संकेतक लगाए गए हैं। चिकित्सा सहायता के लिए दादर स्टेशन पर डॉक्टर, प्राथमिक उपचार और एम्बुलेंस सहित 24ग्7 सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। पश्चिम रेलवे के दादर स्टेशन परिसर में प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है और कम रोशनी वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त लाइटें लगाई गई हैं ताकि उचित दृश्यता सुनिश्चित की जा सके।

पश्चिम रेलवे सभी अनुयायियों से धैर्य बनाए रखने और अपनी यात्रा के दौरान सहयोग करने की अपील करता है। महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर सभी आगंतुकों को सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित अनुभव सुनिश्चित करने हेतु पश्चिम रेलवे आवश्यक सुविधाएँ, समय पर मार्गदर्शन और आवश्यक सहायता प्रदान करने के प्रति पूर्णतया प्रतिबद्ध है।

भारतीय रेलवे चौथे काशी तमिल संगमम के लिए तमिलनाडु से वाराणसी के लिए सात विशेष ट्रेनें चला रहा है

(जीएनएस)।

भारतीय रेलवे कन्याकुमारी, चेन्नई, कोयंबटूर और वाराणसी के बीच सात विशेष रेलगाडियों का संचालन कर रहा है ताकि चौ थे काशी तमिल संगमम में बड़े पैमाने पर भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और तमिल भाषी क्षेत्र व काशी के प्राचीन आध्यात्मिक केंद्र के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और सुदृढ़ किया जा सके। इन विशेष ट्रेनों को इस बहु-दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए निर्बाध यात्रा, आरामदायक लंबी दूरी की कनेक्टिविटी और समय पर आगमन सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किया गया है।

29 नवंबर 2025 को कन्याकुमारी से पहली ट्रेन के रवाना होने के साथ इन सेवाओं की शुरूआत हुई थी। इसके बाद आज चेन्नई से एक अतिरिक्त विशेष ट्रेन रवाना हुई। अगली प्रस्थान 3 दिसंबर को कोयंबटूर से, 6 दिसंबर को चेन्नई से, 7 दिसंबर को कन्याकुमारी से, 9 दिसंबर को कोयंबटूर से और 12 दिसंबर 2025 को चेन्नई से एक और सेवा निर्धारित है। इन नियोजित प्रस्थानों के साथ, तमिलनाडु के प्रमुख शहरों से बनारस के लिए कुल सात विशेष ट्रेनें एक सुव्यवस्थित और चरणबद्ध तरीके से चलेंगी।

समय पर वापसी की यात्रा सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रेलवे ने बनारस से कई विशेष रेलगाडियों की व्यवस्था की है। इनमें 5 दिसंबर को कन्याकुमारी, 7 दिसंबर को चेन्नई और 9 दिसंबर को कोयंबटूर के लिए ट्रेन शामिल हैं। इसके अलावा 11 दिसंबर को चेन्नई, 13 दिसंबर को कन्याकुमारी, 15 दिसंबर को कोयंबटूर और 17 दिसंबर 2025 को चेन्नई के लिए भी अतिरिक्‍त रेलगाड़ियां चलेंगी।

आज से शुरू हो रहा काशी तमिल संगमम का चौथा संस्‍करण तमिलनाडु और काशी के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंध को निरंतरता देता है। यह संस्करण "आइए तमिल सीखें-तमिल करकलम" विषय पर केंद्रित है, जो वाराणसी के स्कूलों में तमिल शिक्षण पहल, काशी क्षेत्र के छात्रों के लिए तमिलनाडु के अध्ययन दौरों और तेनकाशी से काशी तक प्रतीकात्मक ऋषि अगस्त्य वाहन अभियान के माध्यम से दोनों क्षेत्रों के बीच भाषाई और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है।

काशी तमिल संगमम 4.0, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सार को दशार्ता है जो लोगों को अपनी संस्कृति के अलावा अन्‍य समृद्ध संस्कृतियों को समझने और उसकी सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह पहल शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित है जिसमें आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्रमुख ज्ञान भागीदार के रूप में शामलि हैं। रेलवे सहित दस मंत्रालयों की भागीदारी से, यह कार्यक्रम दोनों क्षेत्रों के छात्रों, कारीगरों, विद्वानों, आध्यात्मिक गुरुओं, शिक्षकों और सांस्कृतिक कार्यकताओं को एक साथ जोड़ता है, जिससे उनके बीच विचारों, सांस्कृतिक विधियों और पारंपरिक ज्ञान का आदान-प्रदान सुगम होता है।

इन सात विशेष रेलगाड़ियों के माध्‍यम से सांस्कृतिक रूप से समृद्ध इस यात्रा कार्यक्रम का समन्वय कर, भारतीय रेलवे देश के विविध क्षेत्रों को जोड़ने तथा तमिलनाडु व काशी के बीच साझा विरासत को सुदृढ़ करने में एक केंद्रीय भूमिका निभा रहा है।

मछुआरों की सुरक्षा हेतु बीमा की सुविधा और समुद्री सीमा में बचाव हेतु फिशिंग वेसल्स पर 1 लाख जियो फेसिंग ट्रांसपोंडर लगाने का काम प्रगति पर

(जीएनएस)।

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा और संरक्षा को सर्वोपरि महत्व देती है और अपनी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (ढटटर) के तहत समुद्र में मत्स्यन के दौरान और प्रतिकूल मौसम की स्थिति में मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को (i) पारंपरिक और मोटोराइज्ड फिशिंग वेसल्स के मछुआरों को जीपीएस, लाइफ जैकेट, लाइफबॉय और अन्य जीवन रक्षक उपकरणों, रडार रिफ्लेक्टर, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, फ्लेयर्स का सेट, बैकअप बैटरी, सर्च और रेस्क्यू बीकन आदि से युक्त सुरक्षा किट, (ii) फिशिंग वेसल्स पर कम्यूनिकेशन और ट्रैकिंग उपकरण, (iii) पोटेंशियल फिशिंग जोन (ढन्ने) उपकरण आदि प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विगत पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार ने ढटटर के

तहत 50.05 करोड़ रुपए की कुल लागत से समुद्री मछुआरों को 14,300 संचार(कम्यूनिकेशन) उपकरणों की आपूर्ति के लिए विभिन्न तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रस्तावों को स्वीकृति दी है।

ढटटर अन्य बातों के साथ-साथ मछुआरों को मृत्यु और शारीरिक अक्षमता पर बीमा कवर और फिशिंग वेसल्स के बीमा के लिए बीमा प्रीमियम अनुदान (सबवेनशन) प्रदान करता है। मछुआरों को प्रदान की जाने वाली बीमा कवरेज में शामिल हैं (i) मृत्यु या स्थायी पूर्ण शारीरिक अक्षमता के लिए ₹5.00 लाख, (ii) स्थायी आंशिक शारीरिक अक्षमता के लिए ₹2.50 लाख और (iii) अस्पताल में भर्ती होने पर खर्च के लिए ₹25,000/- का कवरेज। फिशिंग वेसल्स के बीमा के लिए बीमा प्रीमियम में छूट, हल्ल, मशीनरी, फिशिंग नेट सहित एक्सेसरीज के नुकसान, कलिशन लायबिलिटी, कुल नुकसान, आंशिक नुकसान और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए है। विगत तीन वर्षों (2021-22 से 2023-24) और वर्तमान वित्तीय वर्ष (2024-25) के दौरान, ढटटर के तहत प्रतिवर्ष औसतन 32.82 लाख मछुआरों के साथ कुल 131.30 लाख मछुआरों को बीमा कवरेज प्रदान किया गया है।

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार ने प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (ढटटर) के तहत सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फिशिंग वेसल्स पर ट्रांसपोंडर लगाने के लिए कुल 364 करोड़ रुपए की लागत से वेसल कम्युनिकेशन और सपोर्ट सिस्टम (ठफ्रउरर) के नेशनल रोलआउट के एक और प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। 100% सरकारी सहायता से कुल एक लाख फिशिंग वेसल्स पर ट्रांसपोंडर्स लगाए जा रहे हैं। ट्रांसपोंडर में जियो-फेंसिंग फीचर हैं और ये मछुआरों को समुद्री सीमा के पास पहुँचने या उसे पार करने पर अलर्ट देते हैं ताकि समुद्री सीमा पार करने की ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। ठफ्रउरर परियोजना के तहत, अब तक मरीन फिशिंग वेसल्स पर कुल 45051 ट्रांसपोंडर लगाए जा चुके हैं, इसमें तमिलनाडु में ब्लू रिवोल्यूशन स्कीम के तहत लगाए गए 3,884 ट्रांसपोंडर भी शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, तटीय राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मत्स्यपालन विभाग, भारतीय तटरक्षक के साथ मिलकर नियमित रूप से मछुआरों के साथ सामुदायिक संवाद कार्यक्रम/कम्युनिटी इंटरैक्शन प्रोग्राम (उक्द्धर) कर रहे हैं, ताकि उन्हें समुद्र में जीवन सुरक्षा के महत्व, जीवन रक्षक इक्विपमेंट ले जाने, पोर्टेबल कम्युनिकेशन सेट के उपयोग के बारे में जागरूक किया जा सके और उन्हें समुद्री सीमा न लांघने के लिए प्रेरित किया जा सके।

ये जानकारी मत्स्य, पशुपालन और डेरी मंत्रालय के मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भारत सरकार की हिस्सेदारी की बिक्री की पेशकश को लेकर जबरदस्त रूचि देखी गई

(जीएनएस)।

भारत सरकार ने 1 दिसंबर, 2025 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) में अपनी 6.0 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी का विनिवेश करने का निर्णय लिया। इसमें 5 प्रतिशत इक्विटी और अतिरिक्त 1 प्रतिशत ग्रीनशू विकल्प के तौर पर शामिल है, जिसकी फ्लोर प्राइस 54.0 रुपये प्रति शेयर निर्धारित की गई है। कुल पेशकश में से 10 प्रतिशत हिस्सेदारी खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित है, जबकि शेष गैर-खुदरा निवेशकों को आवंटित की जाएगी।

2 दिसंबर, 2025 को, गैर-खुदरा निवेशकों के लिए बोली के पहले दिन, ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) को लेकर जबरदस्त रूचि देखी गई। यह निर्गम आधार के आकार से 4.07 गुना अधिक सब्सक्राइब हुआ, जो बाजार के प्रबल विश्वास को दशार्ता है। ओवरसब्सक्रिप्शन को देखते हुए, सरकार ने ग्रीनशू विकल्प का पूर्ण इस्तेमाल किया, जिससे बीओएम की प्रदत्त पूंजी का कुल विनिवेश 6.0 प्रतिशत हो गया। इससे यह सुनिश्चित होगा कि बीओएम न्यूनतम सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग (एमपीएस) मानदंडों को पूरा करे।

आज की सफल गैर-खुदरा बोली प्रक्रिया के बाद, ओएफएस 3 दिसंबर, 2025 (बुधवार) को खुदरा निवेशकों और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कर्मचारियों के लिए खुल जाएगा। सरकार ने पात्र निवेशकों को इस पेशकश में भाग लेने और सार्वजनिक संपत्तियों के मूल्य निर्माण में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

डीआरआई ने ई-सिगरेट तस्करी गिरोह के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया, तूतीकोरिन में 10.42 करोड़ रुपये मूल्य की 45,984 ई-सिगरेट जब्त की, 3 गिरफ्तार

(जीएनएस)।

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने तूतीकोरिन बंदरगाह पर 10.41 करोड़ रुपये की प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट से जुड़े एक बड़े तस्करी रैकेट का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है। इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

डीआरआई अधिकारियों को विशिष्ट खुफिया जानकारी मिली थी कि ई-सिगरेट की तस्करी में शामिल एक गिरोह ने छतरी के साथ तूतीकोरिन बंदरगाह के माध्यम से चीन से ई-सिगरेट वाले एक कंटेनर को भारत में आयात करने की योजना बनाई है। उक्त जानकारी के आधार पर डीआरआई के अधिकारियों ने 27 नवंबर, 2025 को तूतीकोरिन में उक्त कंटेनर को रोका और उसकी जांच की।

उक्त कंटेनर की जांच के दौरान, कुछ डिब्बों में छतरियों का घोषित कार्गो पाया गया, जबकि एक बड़े हिस्से में छुपा कर रखी गई ई-सिगरेट पाई गई। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत 27

नवंबर, 2025 को 4.30 लाख रुपये मूल्य के 4,300 छतरियों के साथ छुपाई गई मिश्रित स्वादों की कुल 45,984 ई-सिगरेट मिलीं, जिनकी कुल कीमत 10.41 करोड़ रुपये है।

तेजी से कार्रवाई करते हुए, अधिकारियों ने खेप को ले जाने में शामिल चेन्नई के तीन व्यक्तियों को पकड़ लिया और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया।

ई-सिगरेट का आयात इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019 (पीईसीए अधिनियम) के साथ पठित डीजीएफटी अधिसूचना सं. 20/2015-2020 दिनांक 26 सितंबर, 2019 के तहत और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित है।

डीआरआई देश भर में निरंतर सतर्कता और प्रवर्तन की कार्रवाइयों के माध्यम से ई-सिगरेट जैसे प्रतिबंधित और हानिकारक सामानों की तस्करी पर अंकुश लगाकर देश के आर्थिक हितों और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

एमएसएमई के लिए ऋण मूल्यांकन को डिजिटल रूप से सुदृढ़ बनाने हेतु सरकार ने क्रेडिट असेसमेंट मॉडल का शुभारंभ किया

डिजिटल भुगतान लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू की गईं

(जीएनएस)।

सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए क्रेडिड असेसमेंट मॉडल (सीएएम) का शुभारंभ किया है। यह मॉडल इकोसिस्टम में उपलब्ध डिजिटल रूप से प्राप्त एवं सत्यापित किए जा सकने वाले डेटा का उपयोग करता है तथा सभी ऋण आवेदनों के मूल्यांकन के लिए वस्तुलिस्ट निर्णय-आधारित स्वाचालित प्रक्रियाएं विकसित करता है। इसके तहत बैंक के मौजूदा ग्राहकों एवं नए ग्राहकों दोनों प्रकार के एमएसएमई ऋणकताओं के लिए मॉडल आधारित सीमा निर्धारण किया जाता है।

सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) डिजिटल भुगतान लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहलें कर रहे हैं। इनमें अन्य के साथ-साथ रुपे डेबिट कार्ड एवं कम मूल्य के बीएचआईएम-यूपीआई (पी2एम) लेनदेन को प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन योजना तथा पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (पीआईडीएफ) शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, पहली जून, 2020 को शुरू की गई प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम-एसवीएनिधि) योजना को अब 31 मार्च, 2030 तक बढ़ा दिया गया है, जिसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा वित्तीय सेवा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को उनके कारोबार में सहायता हेतु दिए जाने वाले ऋण को तीन किस्तों में क्रमशः 15,000 रुपये, 25,000 रुपये और 50,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। योजना में शामिल अन्य सुविधाओं में यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड, जिसकी क्रेडिट सीमा 30,000 रुपये होगी तथा डिजिटल लेनदेन पर कैशबैक प्रोत्साहन शामिल हैं।

केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन और मिलावट नियंत्रण को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम

47 राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को उन्नत किया गया है और सॉफ्टेल योजना के तहत 34 माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने परीक्षण की बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करने के लिए एफएसएसएआई के समर्थन से 305 मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं खरीदी हैं

(जीएनएस)।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने तथा मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने का अधिकार है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन और प्रवर्तन केंद्र और राज्य सरकारों की साझा ज़िम्मेदारी है। जहाँ एफएसएसएआई, विज्ञान-आधारित मानक निर्धारित करने और समग्र समन्वय सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार है, वहीं राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण मुख्य रूप से क्षेत्रीय स्तर पर प्रवर्तन के लिए ज़िम्मेदार हैं।

अधिनियम और खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियमों (एफएसएसआर) के तहत निर्धारित मानकों, सीमाओं और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, एफएसएसएआई, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों और अपने चार क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से, नियमित रूप से स्थानीयकृत/लक्षित विशेष प्रवर्तन और निगरानी अभियान चलाता है। खाद्य सुरक्षा के दायरे को समझने के लिए आँकड़े एकत्र करने और फिर खाद्य सुरक्षा निगरानी, जोखिम मूल्यांकन और मानक निर्धारण के लिए प्रासंगिक आँकड़े प्रदान करने हेतु, समय-समय पर मुख्य खाद्य पदार्थों और मिलावट की संभावना वाली वस्तुओं पर व्यवस्थित तरीके से निगरानी कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

एफएसएसएआई ने खाद्य नमूनों के परीक्षण के लिए 246 राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन बोर्ड प्रत्यायन प्रयोगशालाओं (एनएबीएल) को अधिसूचित किया है। इसके अतिरिक्त, अपीलीय नमूनों के विश्लेषण के लिए 24 रेफरल खाद्य प्रयोगशालाओं को भी अधिसूचित किया गया है, जो मुख्यतः केंद्र सरकार के विभागों और संस्थानों के स्वामित्व में हैं।

इसके अलावा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य परीक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, एफएसएसएआई ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को "देश में खाद्य परीक्षण प्रणाली को मजबूत करना जिसमें मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का प्रावधान शामिल है" (सॉफटेल) योजना के तहत तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की है । इस योजना के तहत, 47 राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को उन्नत किया गया है और खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मापदंडों के क्षेत्र में 34 माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। परीक्षण क्षमताओं में अंतर को पाटने और दूरदराज के क्षेत्रों में मौके पर खाद्य परीक्षण के लिए आउटरीच का विस्तार करने के लिए, जहां प्रयोगशाला के बुनियादी ढांचे की कमी है, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों ने मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (एमएफटीएल) को तैनात किया है। अब तक, 541 एमएफटीएल के लिए एफएसएसएआई द्वारा दी गई धनराशि के बदले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 305 एमएफटीएल खरीदे और तैनात किए गए हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिदेर्शों में बैंकों को क्षेत्रीय भाषाओं में ग्राहक सेवाएँ प्रदान करने के निर्देश सम्मिलित हैं

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को त्रिभाषी सामग्री जारी करने, स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति करने और प्रभावी ग्राहक संपर्क के लिए कर्मचारियों की स्थानीय भाषा दक्षता सुनिश्चित करने का परामर्श दिया गय है

(जीएनएस)।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के ग्राहक सेवाओं पर बैंकों को जारी दिशानिर्देश, क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग पर व्यापक निर्देश प्रदान करते हैं ताकि बैंक क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार अपनी सेवा प्रदान कर सकें। बैंकों को शाखाओं के सामान्य प्रबंधन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनाने का भी परामर्श दिया गया है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सभी काउंटरों पर संकेतक बोर्ड प्रदर्शित करना, ग्राहकों को बैंक में उपलब्ध सेवाओं और सुविधाओं के सभी विवरणों वाली पुस्तिकाएँ प्रदान करना, खुदरा ग्राहकों द्वारा उपयोग किए जाने वाली सभी मुद्रित सामग्री जैसे कि खाता खोलने के फॉर्म, भुगतान पर्ची, पासबुक आदि उपलब्ध कराना, ग्राहक निवारण आदि को हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अलावा, बैंकों के पास क्षेत्रीय भाषाओं में बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने और सहायता प्रदान करने के लिए बहुभाषी संपर्क केंद्र और डिजिटल चैनल हैं।

वित्तीय सेवा विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को बैंकों में ग्राहक सेवा के बारे में संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग पर भारतीय रिजर्व बैंक के निदेर्शों का पालन करने का भी परामर्श दिया है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को भेजे अपने पत्र में फिर से कहा है कि ग्राहकों को सभी पत्र-व्यवहार अनिवार्य रूप से त्रिभाषी प्रारूप - हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में जारी किए जाने चाहिए। साथ ही, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भेजे अपने पत्र में परामर्श दिया है कि वे स्थानीय ग्राहकों के साथ उनकी स्थानीय भाषा में, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों में, प्रभावी संचार सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय बैंक अधिकारियों (एलबीओ) की भर्ती के लिए एक नीति बना सकते हैं, और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इसका सक्रिय रूप से पालन किया जा रहा है। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ग्राहक सेवा का कार्य मुख्य रूप से ग्राहक सेवा सहयोगियों (सीएसए) द्वारा किया जाता है, जहाँ भर्ती प्रक्रिया के दौरान, सीएसए को अब उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा के लिए एक स्थानीय भाषा प्रवीणता परीक्षा (एलपीटी) उत्तीर्ण करनी होगी जहाँ कर्मचारी तैनात होंगे। इससे क्षेत्रीय भाषाओं में निर्बाध संचार की सुविधा मिलती है और इससके परिणामस्वरूप प्रभावी ग्राहक सेवाएं मिलती हैं।

वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI

सम्पादकीय

एसआईआर में हो रही जल्दबाजी पर टीएमसी को आपत्ति

टीएमसी की अतिशियोक्ति चुनाव आयोग के हाथ खून से सने हैं, यह कहना है तृणमूल कांग्रेस के उस प्रातिनिधिमंडल का जो चुनाव आयोग की पूरी बैंच के साथ दो दिन पहले मिला था। पमि बंगाल में जारी वोटर लिस्ट में बदलाव की प्राव्रिया के बीच तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ ब्रायन के नेतृत्व में पाटा के दस सदस्यीय प्रातिनिधिमंडल ने आयोग से मुलाकात की। ओ ब्रायन ने मीटिग के बाद कहा कि पाटा ने चुनाव आयोग के सामने पांच सवाल उठाए, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश वुमार ने उनका कोई जवाब नहीं दिया। तृणमूल के सांसदों का कहना था कि यदि एसआईआर का उद्देश्य नकली वोटरों और घुसपैठियों का पता लगाना है तो फिर बंगाल ही क्यों? मेघालय और त्रिपुरा में क्यों नहीं? जबकि इन राज्यों की सीमाएं भी बांग्लादेश से मिलती हैं।

हालांकि तृणमूल कांग्रेस सांसदों को सुनने के बाद आयोग ने स्पष्ट किया कि एसआईआर सभी राज्यों में होना है। डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि हम इन एसआईआर की संवैधानिक वैधता पर सवाल नहीं उठा रहे हैं बल्कि उस तरीके पर सवाल उठा रहे हैं, जिस तरीके से जल्दबाजी में इसे लागू किया जा रहा है उस पर एतराज है। एसआईआर के लिए उन्होंने समय बढ़ाने के लिए भी मांग की। तृणमूल कांग्रेस के प्रातिनिधिमंडल ने जब शुव्रवार को चुनाव आयोग की पूरी पीठ से मुलाकात की तो उन्होंने खुलकर आरोप लगाया कि पमि बंगाल में एसआईआर के कारण कम से कम 40 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के हाथ खून से सने हैं। हमने 5 सवाल उठाए और चुनाव आयोग ने एक घंटे तक बिना रूके हमसे बात की। जब हम बोल रहे थे तब हमें भी नहीं टोका गया लेकिन हमारे पांच सवालों में से किसी का भी जवाब नहीं मिला। लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने बताया कि प्रातिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर उन्हें 40 ऐसे लोगों की सूची सौंपी जिनकी मौत कथित तौर पर एसआईआर प्राव्रिया से जुड़ी थी। हालांकि उन्होंने कहा कि आयोग ने इन्हें केवल आरोपी कहकर खारिज कर दिया। सांसदों की चुनाव आयोग से करीब 40 मिनट में कल्याण बनजा, महुआ मोइत्रा और ममता बाला ठावुर ने अपनी बात रखी और जो कहना था वो कहा। उन्होंने कहा, इसके बाद सीईसी ने एक घंटे तक बिना रूके बात की। जब हम बोल रहे थे तब हमें भी नहीं टोका गया, लेकिन हमें हमारे पांच सवालों में से किसी एक का भी जवाब नहीं मिला। एसआईआर के दूसरे चरण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। टीएमसी सांसदों के प्राश्नों का संतोषजनक जवाब न देना इस प्राव्रिया के औचित्य और उपलब्धता पर सवाल उठ रहा है। एसआईआर से जुड़े संदेहों का दूर न होना शुभ संकेत नहीं है। एसआईआर के राजनीतिक पहल को समझा जा सकता है। खासकर बंगाल में जहां भाजपा और तृणमूल की कड़ी टक्कर होने का अंदाजा है। लेकिन इससे जुड़ी चिताओं को भी खारिज नहीं कर सकते। एसआईआर की प्रासंगिकता पर कोई सवाल नहीं है और न ही आयोग के अधिकार पर। सुप्रीम कोर्ट भी यह बात कह चुका है। लेकिन विपक्ष की चिताओं को दूर करना भी आयोग की ही जिम्मेदारी है। विपक्ष को अगर लग रहा है कि उनकी बातों को अनसुना किया जा रहा है तो देश की इस संवैधानिक संस्था को न केवल इनका संतोषजनक जवाब देना होगा। बल्कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव प्राव्रिया भी अपनानी होगी।

साइबर सुरक्षा अवसंरचना:पूरे देश में एक समेकित और नियामत प्रणाली

(जीएनएस)।

सरकार ने साइबर खतरों से निपटने के लिए पूरे देश में एक समेकित और नियामत प्रणाली बनाई है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट (एनएससीएस) के तहत नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर (एनसीएससी) अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल पक्का करता है, जबकि इंडियन साइबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (क्वसी) साइबर अपराध से नियामक और असरदार तरीके से निपटता है।

इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (सीईआरटी-इन) को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) कानून, 2000 के सेक्शन 70बी के प्रावधान के तहत साइबर सुरक्षा की घटनाओं पर जवाब देने के लिए नेशनल एजेंसी बनाया गया है। सीईआरटी-इन, प्रोएक्टिव खतरे को कम करने के लिए अलग-अलग क्षेत्र के संगठनों के साथ खास अलर्ट शेयर करने के लिए एक ऑटोमेटेड साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म चलाता है। सीईआरटी-इन द्वारा लागू किया गया नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीसीसी), साइबर सिक्योरिटी खतरों का पता लगाने के लिए साइबरस्पेस की जांच करता है। यह एक्शन लेने के लिए संबंधित ऑर्गनाइजेशन, राज्य सरकारों और स्टेकहोल्डर एजेंसियों के साथ जानकारी शेयर करता है। सीईआरटी-इन समय-समय पर लेटेस्ट साइबर खतरों/कमजोरियों के बारे में अलर्ट और एडवाइजरी जारी करता है।

सरकार ने आईटी कानून, 2000 के सेक्शन 70ए के प्रावधान के तहत देश में क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (एनसीआईआईपीसी) भी बनाया है। एनआईसी, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और ज़िला प्रशासन के मंत्रालयों, डिपार्टमेंट और एजेंसियों को अलग-अलग ई-गवर्नेंस सॉल्यूशन के लिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) सहायता देता है और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड और प्रैक्टिस के हिसाब से इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी और प्रैक्टिस को फॉलो करता है, जिसका मकसद साइबर अटैक को रोकना और डेटा को सुरक्षित रखना है।

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने साइबर क्राइम, साइबर जासूसी, साइबर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी के खतरों, नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ नई टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल और इसी तरह की चिंताओं से असरदार तरीके से निपटने के लिए आईबी, सीआईआरए, डीसीवाईए, डीओटी, सीईआरटी-इन, क्वसी, एनसीआईआईपीसी और एनआईसी जैसी भागीदार एजेंसियों के साथ एमएसी (मल्टी एजेंसी सेंटर) प्लेटफॉर्म के तहत सीवाईएमएसी (साइबर मल्टी एजेंसी सेंटर) बनाया है। सीवाईएमएसी प्लेटफॉर्म सभी साइबर सिक्योरिटी एजेंसियों में साइबर रेजिलिएंस बढ़ाने के लिए एक यूनिफाइड और स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है। रियल-टाइम मॉनिटरिंग, थ्रेट इंटेलिजेंस शेयरिंग और कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स क्षमताओं को इनेबल करके, यह साइबर सिक्योरिटी रिस्क को असरदार तरीके से मैनेज करने के लिए प्रोएक्टिव डिटेक्शन और एनालिसिस और कोलेबोरेटिव अप्रोच पक्का करता है। सभी एजेंसियों को नेशनल साइबर डिफेंस को मजबूत करने और इंडियन इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (आईसीटी) इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए इस सिस्टम के साथ पूरी तरह इंटीग्रेट होने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है।

असम में एक नई नेशनल साइबर फोरेंसिक (इन्वेस्टिगेशन) लैबोरेटरी बनाई गई है, ताकि मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट रीजन और सिक्किम में काम करने वाले सभी एलईए को साइबर फोरेंसिक सुविधाएं दी जा सकें और उनकी डिजिटल इन्वेस्टिगेशन क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। यह 29.08.2025 से चालू है।

नेशनल साइबर फोरेंसिक (इन्वेस्टिगेशन) लैबोरेटरी त्रएनसीएफएल(क)त्र, एक 'स्टेट-ऑफ-द-आर्ट' फैसिलिटी है, जिसे 2019 में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (क्वसी) के तहत द्वारका, नई दिल्ली में एलईए और दूसरी सेंट्रल एजेंसियों को जांच के दौरान फोरेंसिक मदद देने के लिए बनाया गया है। एनसीएफएल की सेवाओं या सुविधाओं का इस्तेमाल देश भर के राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर रहे हैं। 31.10.2025 तक, एनसीएफएल ने साइबर क्राइम से जुड़े लगभग 12,952 साइबर मामलों में राज्य एलईए को अपनी सर्विसेज दी हैं। 31.10.2025 तक, 2118 एलईए के लोगों को नवीनतम फोरेंसिक टूल्स और टेक्नीक्स की ट्रेनिंग दी जा चुकी है।

राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में साइबर फोरेंसिक लैब्स महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम प्रिवेंशन (सीसीपीडब्ल्यूसी) स्कीम के तहत बनाई गई थीं, जिसे 2018 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत, गृह मंत्रालय ने साइबर फोरेंसिक कंसल्टेंट्स बनाने के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को 131.60 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी थी। 33 राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों में साइबर फोरेंसिक-कम-ट्रेनिंग लैब्स शुरू की गई हैं।

सीईआरटी-इन, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में तालमेल और जानकारी शेयर करने में मदद के लिए नॉर्थ-ईस्टर्न इलाके समेत राज्यों में ड्रिल के साथ वर्कशॉप करता है।

इंडियन साइबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (क्वसी) के तहत मेवात, जामताड़ा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापत्तनम और गुवाहाटी के लिए सात जॉइंट साइबर कोऑर्डिनेशन टीम (जेसीसीटी) बनाई गई हैं। ये टीमें पूरे देश को कवर करती हैं। ये टीमें साइबर क्राइम हॉटस्पॉट/मल्टी-ज्यूरिस्डिक्शनल मामलों वाले इलाकों के आधार पर काम करती हैं। इसके लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया है ताकि राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेश की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क को बेहतर बनाया जा सके।

समन्वय प्लेटफॉर्म को साइबर क्राइम डेटा शेयरिंग और एनालिटिक्स के लिए एक मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एमआईएस) प्लेटफॉर्म, डेटा रिपॉजिटरी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों (एलईए) के लिए एक तालमेल मंच के तौर पर काम करने के लिए चालू किया गया है। यह अलग-अलग राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेश में साइबर अपराध की शिकायतों में शामिल अपराधों और अपराधियों के एनालिटिक्स आधारित इंटरस्टेट लिंकेज देता है। मॉड्यूल 'प्रतिबिंब' अपराधियों की जगहों और क्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर को मैप पर दिखाता है ताकि अधिकार क्षेत्र के अधिकारियों को उनकी जानकारी मिल सके। यह मॉड्यूल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को क्वसी और दूसरे एसएमई से टेक्नो-लीगल मदद मांगने और पाने में भी मदद करता है। इससे 16,840 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और 1,05,129 साइबर जांच मदद का अनुरोध किया गया है।

मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (एमओओसी) प्लेटफॉर्म, जिसका नाम 'सीवाईट्रेन' है, साइबर अपराध जांच, फोरेंसिक और प्रॉसिक्यूशन में पुलिस और न्यायिक अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए है। यह प्रमाणपत्र देने के साथ मानक ऑनलाइन कोर्स देता है, जिससे सभी एजेंसियों में एक जैसा कौशल विकास पक्का होता है। 31.10.2025 तक पोर्टल के जरिए 1,44,895 पुलिस अधिकारी/जज/प्रॉसिक्यूटर/सीपीओ/सीएपीएफ रजिस्टर्ड हैं और 1,19,628 सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं।

यह जानकारी गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री बंदी संजय कुमार ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में दी।

'डिस्ट्रिक्ट्स ऐज एक्सपोर्ट हब्स' पहल, दक्षिण कन्नड़ को जिला निर्यात केंद्र घोषित

सरकार ने 'डिस्ट्रिक्ट्स ऐज एक्सपोर्ट हब्स' पहल के अंतर्गत दक्षिण कन्नड़ को जिला निर्यात केंद्र घोषित किया

समुद्री खाद्य और काजू निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण कन्नड़ को जिला निर्यात केंद्र नामित किया गया

प्रविष्टि तिथि: 02 ऊएउ 2025 5:07ढटु८ ढक्ष ऊ

सरकार ने 'डिस्ट्रिक्ट्स ऐज एक्सपोर्ट हब्स' पहल के अंतर्गत दक्षिण कन्नड़ को जिला निर्यात केंद्र के रूप में नामित किया है, जिसमें समुद्री खाद्य और काजू को संभावित निर्यात उत्पादों के रूप में शामिल किया गया है। यह मान्यता जिले की प्रबल निर्यात क्षमता को रेखांकित करती है और देश भर में संतुलित एवं सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के चल रहे प्रयासों के अनुरूप है। इस पहल के अंतर्गत पहचाने गए केन्द्रित क्षेत्रों से स्थानीय उद्योग को और मजबूत करने, मूल्यवर्धित गतिविधियों को बढ़ाने और क्षेत्र में उद्यमों के लिए बाजार के अवसरों का विस्तार करने की उम्मीद है। इस प्रयोजन का उद्देश्य वैश्विक व्यापार में बढ़ती भागीदारी को बढ़ावा देना और जिले के भीतर दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देना है।

रसद संबंधी व्यवधानों का सामना कर रहे निर्यातकों के लिए सहायता: डीईएच पहल के अंतर्गत, सरकार ने रसद दक्षता बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और माल ढुलाई में अस्थिरता से उत्पन्न होने वाली कमजोरियों को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं। प्रमुख हस्तक्षेपों में शामिल हैं:

1. जिला निर्यात कार्य योजना (डीईएपी): जिला स्तर पर सुधार के लिए लक्षित सिफारिशों के साथ संपर्क संबंधी मुद्दों, भंडारण घाटे, पैकेजिंग और परीक्षण बुनियादी ढांचे जैसे रसद अंतरालों की पहचान।
2. एसईपीसी और डीईपीसी का संचालन: राज्य और जिला निर्यात संवर्धन समितियां, जिला प्राधिकारियों, सीमा शुल्क, लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं, एमएसएमई निकायों और उद्योग संघों के बीच समन्वित कार्रवाई की सुविधा प्रदान करती हैं ताकि लॉजिस्टिक्स मुद्दों का शीघ्र समाधान किया जा सके।
3. बुनियादी ढांचे और रसद में वृद्धि: उपायों में संपर्क में सुधार, सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना, भंडारण और परीक्षण सुविधाओं को बढ़ाना और बंदरगाहों और शुष्क बंदरगाहों के साथ संपर्क को मजबूत करना शामिल है।
4. ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा: अमेजन, शिपरॉकेट और डीएचएल जैसे प्लेटफार्मों के साथ साझेदारी एमएसएमई को माल ढुलाई दर में अस्थिरता के विपरीत बफर करने के लिए लागत प्रभावी कूरियर और छोटे-खेप शिपिंग विकल्प प्रदान करती है।
5. डाक घर निर्यात केंद्र (डीएनके): दस्तावेजीकरण, पैकेजिंग और छोटे पार्सल शिपमेंट के लिए डाक निर्यात सुविधाओं का विस्तार, रसद व्यवधानों के दौरान वैकल्पिक चैनल प्रदान करना।
6. क्षमता निर्माण और आउटरीच: डीजीएफटी क्षेत्रीय प्राधिकरण और जिला प्रशासन लॉजिस्टिक्स योजना, निर्यात प्रक्रियाओं, पैकेजिंग मानदंडों और अनुपालन आवश्यकताओं पर निर्यातक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं।
7. निर्यात निष्पादन की निगरानी: उभरती चुनौतियों की पहचान करने और उत्तरदायी हस्तक्षेप को सक्षम करने के लिए जिलावार निर्यात आंकड़ों का नियमित रूप से विश्लेषण किया जाता है।

निर्यात केंद्र के रूप में ज़िले (डीईएच) पहल के अंतर्गत , सरकार ज़िला-विशिष्ट निर्यात बाधाओं की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए एक सुनियोजित प्रक्रिया अपना रही है, जिसमें रसद, संपर्क और भंडारण से संबंधित बाधाएं भी शामिल हैं। दक्षिण कन्नड़ ज़िले के लिए, एक ज़िला निर्यात कार्य योजना (डीईएपी) तैयार की गई है, जिसमें बेहतर निर्यात बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें न्यू मैंगलोर बंदरगाह तक बेहतर संपर्क, भंडारण और समेकन सुविधाओं का विस्तार, और पहचाने गए निर्यात उत्पादों के लिए सहायक बुनियादी ढांचा शामिल है।

इसके अलावा, जिला अधिकारियों, निर्यातकों, बंदरगाह प्राधिकरण, सीमा शुल्क, रसद एजेंसियों और संबंधित राज्य एवं केंद्रीय विभागों के बीच समन्वित कार्रवाई को सुगम बनाने के लिए एक जिला निर्यात संवर्धन समिति (डीईपीसी) का गठन किया गया है। इस व्यवस्था के माध्यम से, डीईएपी में चिन्हित बुनियादी ढांचे से संबंधित आवश्यकताओं—जिसमें बंदरगाह से जुड़े भंडारण और रसद सहायता शामिल है—को संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ उचित विचार-विमर्श के लिए शुरू किया जा रहा है।

'डिस्ट्रिक्ट्स ऐज एक्सपोर्ट हब्स' पहल एक सुविधाजनक और परामर्शी ढांचे के रूप में कार्य करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिला-स्तरीय निर्यात आवश्यकताओं को क्षेत्र में चल रहे और प्रस्तावित बुनियादी ढांचे के विकास प्रयासों के साथ संरेखित किया जाए, जिसमें न्यू मैंगलोर पोर्ट से जुड़े प्रयास भी शामिल हैं, जिससे दक्षिण कन्नड़ जिले में समग्र निर्यात इकोसिस्टम को मजबूत किया जा सके।

निर्यात केन्द्र के रूप में जिले (डीईएच) पहल एक सुविधाजनक ढांचे के रूप में कार्य करती है जिसका उद्देश्य जिला-स्तरीय निर्यात क्षमता को मजबूत करना और स्थानीय मूल्य-श्रृंखला विकास का समर्थन करना है।

यह पहल नीचे दी गई जागरूकता के माध्यम से स्थानीय स्तर पर मूल्य-श्रृंखलाओं को बनाए रखने में सहायता करती है:

- जिला निर्यात कार्य योजना (डीईएपी): प्रसंस्करण, पैकेजिंग, परीक्षण और रसद में मूल्य-श्रृंखला अंतराल की पहचान।
- संस्थागत समन्वय: डीईपीसी/एसईपीसी बाधाओं को दूर करने के लिए अधिकारियों, निर्यातकों और संबंधित एजेंसियों के बीच अभिसरण की सुविधा प्रदान करते हैं।
- बुनियादी ढांचे और क्षमता निर्माण सुविधा: बिचौलियों पर निर्भरता कम करने के लिए भंडारण, सामान्य सुविधा केंद्र, परीक्षण प्रयोगशालाएं, प्रशिक्षण और बाजार पहुंच सहायता को बढ़ावा दिया जाता है।

वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत 1,97,692 स्टार्टअप्स को मान्यता

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत 1,97,692 स्टार्टअप्स को मान्यता दी
सरकार ने डीपीआईआईटी मान्यता संरचना के माध्यम से स्टार्टअप विकास को सुदृढ़ किया

(जीएनएस)।

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने 31 अक्टूबर 2025 तक स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत 1,97,692 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी है। ये मान्यताएं 19 फरवरी 2019 की जीएसआर अधिसूचना 127 (ई) के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार प्रदान की गई हैं, जो संस्थाओं को स्टार्टअप्स के रूप में वगीकृत करने के मानदंडों को रेखांकित करती हैं।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के अनुसार, 31 अक्टूबर 2025 तक 6,385 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप बंद (अर्थात, भंग/समाप्त) श्रेणी [11 नवंबर 2025 को साझा किए गए आंकड़ों के आधार पर] में हैं। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार बंद (अर्थात, भंग/समाप्त) श्रेणी में आने वाली संस्थाओं की संख्या अनुलग्नक-क में दी गई है।

सरकार ने स्टार्टअप्स के बंद होने की घटनाओं में कोई वृद्धि नहीं देखी है। जो बंद होते हैं, वे आमतौर पर

व्यावसायिक मॉडल की व्यवहार्यता, बाजार की मांगों के साथ संयोजन, घरेलू और वैश्विक आर्थिक स्थितियों, विकसित उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति, वित्तपोषण आकर्षित करने की क्षमता और अन्य व्यवसाय-विशिष्ट कारकों से प्रभावित होते हैं।

स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक पहल है। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार तीन प्रमुख योजनाओं, स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) को कार्यान्वित कर रही है ताकि विभिन्न क्षेत्रों के स्टार्टअप्स को उनके व्यावसायिक चक्र के विभिन्न चरणों में वित्तपोषण के अवसर और सहायता प्रदान की जा सके।

उद्यम पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की निधि के साथ एफएफएस की स्थापना की गई है। इसका संचालन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा किया जाता है, जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) को पूंजी प्रदान करता है, जो बदले में स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं। 31 अक्टूबर 2025 तक कैलेंडर वर्ष 2023, 2024 और 2025 में एआईएफ को प्रतिबद्ध और वितरित राशि अनुलग्नक-क्क में दी गई है।

एसआईएसएफएस इनक्यूबेटरों के माध्यम से सीड स्टेज स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एसआईएसएफएस 1 अप्रैल 2021 से 945 करोड़ रुपये के कोष के साथ प्रचालनगत किया गया है। कैलेंडर वर्ष 2023, 2024 और 2025 में 31 अक्टूबर 2025 तक इनक्यूबेटरों को स्वीकृत और वितरित की गई राशि अनुलग्नक-क्कक में दी गई है।

सीजीएसएस को पात्र वित्तीय संस्थानों के माध्यम से स्टार्टअप्स को बिना किसी गारंटी के ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्रियान्वित किया गया है। सीजीएसएस का संचालन राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) लिमिटेड द्वारा किया जाता है और यह 1 अप्रैल 2023 से चालू हो गया है। कैलेंडर वर्ष 2023, 2024 और 2025 में 31 अक्टूबर 2025 तक स्टार्टअप उधारकताओं को गारंटीकृत ऋणों की राशि अनुलग्नक-क्ष में दी गई है।

यह जानकारी वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

सरकार ने चाय विकास और संवर्धन योजना के माध्यम से असम के चाय सेक्टर को मजबूत किया

चाय बोर्ड द्वारा उत्पादकता और उत्पादक सशक्तिकरण के प्रयासों के साथ असम के चाय उद्योग को बढ़ावा

(जीएनएस)।

भारत सरकार चाय बोर्ड के माध्यम से असम राज्य सहित पूरे देश में चाय विकास एवं संवर्धन योजना (टीडीपीएस) कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ चाय के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना, बाजारों में प्रवेश करने वाली चाय की गुणवत्ता में सुधार करना, निर्यात में वृद्धि करना, छोटे चाय उत्पादकों को स्व-सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों (एसएचजी/एफपीओ) के गठन के लिए संगठित करना है। इससे वे मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ सकेंगे, एसएचजी/एफपीओ द्वारा लघु चाय फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जा सकेंगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकेंगा और क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किए जा सकेंगे। इस योजना के तहत, चाय बोर्ड के कुल बजट में से 152.76 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे और चाय बोर्ड द्वारा 2021-22 से 2025-26 (31.10.2025 तक) की अवधि के दौरान असम राज्य के लिए विशिष्ट गतिविधियों के लिए 150.20 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया गया था।

इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले छोटे उत्पादकों की जिला-वार और वर्ष-वार संख्या का ब्यौरा अनुलग्नक-क के रूप में संलग्न है।

चाय विकास और संवर्धन योजना के तहत, असम राज्य में 2021-22 से 2025-26 (31.10.2025 तक) की अवधि के दौरान की गई गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ 437.42 हेक्टेयर क्षेत्र में चाय का पुनः रोपण; 318 एसएचजी, 143 एफपीओ और 26 एफपीसी का गठन; 31 मिनी चाय कारखानों की स्थापना; चाय बागानों के 30.32 हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक में बदलना; 30 फार्म फील्ड स्कूलों की स्थापना और 1343 क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है। भारतीय चाय का निर्यात, जिसमें असम चाय भी शामिल है, 7.15 प्रतिशत की सीएजीआर के साथ 2021-22 में 751.07 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2024-25 में 923.89 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है।

नीति आयोग के विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) द्वारा 'चाय विकास और संवर्धन योजना (टीडीपीएस)' का मूल्यांकन अध्ययन किया गया था। मई 2023 में प्रस्तुत प्रमुख सिफारिशों के साथ इसकी रिपोर्ट तैयार की गई थी।

रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड की बागान स्कीमों के संतोषजनक कार्यान्वयन के साथ-साथ छोटे चाय उत्पादकों के एसएचजी/एफपीओ के गठन और चाय कारखानों की स्थापना में उनकी सहायता करने में इसकी उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है।

'काशी तमिल संगमम्' से काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों से स्थापित सांस्कृतिक संबंध हो रहे मजबूत : डॉ. एल. मुरुगन

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय मामलों के राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने 02 दिसंबर से वाराणसी में शुरू हो रहे 'काशी तमिल संगमम् 4.0' में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की इकाई केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का किया उद्घाटन

'काशी तमिल संगमम्' प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक महत्वपूर्ण पहल है, इससे राष्ट्र की एकता और अखंडता को मिल रहा है बल : केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन

'काशी तमिल संगमम्' से काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों से स्थापित सांस्कृतिक संबंध हो रहा है और मजबूत: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन

(जीएनएस)।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय मामलों के राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने 02 दिसंबर से वाराणसी के नमो घाट पर शुरू हो रहे 'काशी तमिल संगमम् 4.0' में "काशी एवं तमिल की संस्कृति, महान व्यक्तित्वों एवं केंद्र सरकार के जनकल्याणकारी नीतियों" विषय पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की इकाई केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने कहा कि 'काशी तमिल संगमम्' का आयोजन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक महत्वपूर्ण पहल है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे जहां एक ओर काशी और तमिल की संस्कृति को आपस में जानने का अवसर मिलता है वहीं दूसरी ओर इससे हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को और अधिक मजबूती मिलती है। डॉ. एल. मुरुगन ने कहा कि 'काशी तमिल संगमम्' प्रत्येक वर्ष अलग - अलग विषयों पर आयोजित किया जाता है, यह काशी तमिल संगमम् का चतुर्थ संस्करण है तथा इसका विषय है 'तमिल करकलाम' जिसका अर्थ है आइए तमिल सीखें। केंद्रीय मंत्री ने कहा इस प्रकार के आयोजन से काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों से स्थापित सांस्कृतिक संबंध और भी मजबूत होंगे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किये गये जी.एस.टी. सुधार एवं श्रम कानून सुधारों से देश की आम जनता को अत्यधिक फायदा हो रहा है।

काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने वाले 'काशी तमिल संगमम्' के इस चतुर्थ संस्करण में केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा लगायी गयी चित्र प्रदर्शनी में तमिलनाडु एवं काशी की महान विभूतियों के राष्ट्र निर्माण में योगदान एवं उनकी उपलब्धियां को दशार्या गया है।

जीएलए का 14-वां दीक्षांत समारोह आज, हजारों विद्यार्थियों को मिलेंगी उपाधियां

–समारोह में 21 गोल्ड और 21 सिल्वर मेडलिस्ट मेधावियों को पदक और विभिन्न पाठ्यक्रमों के हजारों सफल विद्यार्थियों को उपाधियां की जाएंगी प्रदान

मथुरा (जीएनएस)। जीएलए विश्वविद्यालय, मथुरा (उ.प्र.) का 14-वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित होगा। इसके लिए मंगलवार को रिहर्सल कर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस संबंध में कुलसचिव अशोक कुमार सिंह ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी और विशिष्ट अतिथि आईआईटी कानपुर भौतिकी विभाग के पूर्व प्रोफेसर पद्मश्री एचसी वर्मा तथा सिप्ला हेल्थ लि. मुंबई के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ शिवम पुरी होंगे। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कुलाधिपति नारायण दास अग्रवाल करेंगे। कुलसचिव ने बताया कि कार्यपरिषद की बैठक में मेडल और डिग्री हांसिल करने वालों के लिए स्वीकृति की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। स्वर्ण पदक समेत विशेष पदकों के विजेताओं की सूची को अंतिम रूप से जांच कर ली गई है। समारोह में 21 गोल्ड और 21 सिल्वर मेडलिस्ट मेधावियों को पदक और सेंटर ऑफ डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन की 1166 डिग्रियों समेत 5548 उपाधियां प्रदान की जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मंच पर विशिष्ट अतिथियों को मानद उपाधि से नवाजा जाएगा। कुलपति प्रो. अनूप कुमार गुप्ता, कुलसचिव अशोक कुमार सिंह समेत अन्य जीएलए विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों ने अपनी-अपनी भूमिकाओं व स्क्रिप्ट का रिहर्सल भी किया।

विश्वविद्यालय के चतुर्दश दीक्षांत समारोह की तैयारियों का जायजा लेते हुए कुलसचिव अशोक कुमार सिंह, साथ में कर्मचारी।

अतिथि का होगा भव्य स्वागत

मथुरा ब्यूरो। (मुकेश कुशवाह) दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी व विशिष्ट अतिथि आईआईटी कानपुर भौतिकी विभाग के पूर्व प्रोफेसर पद्मश्री एचसी वर्मा तथा सिप्ला हेल्थ लि. मुंबई के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ शिवम पुरी पहली बार विश्वविद्यालय के किसी बडे. कार्यक्रम में आ रहे हैं, ऐसे में उनके भव्य स्वागत की तैयारी कर ली गई है। अंतिम दिन तैयारियों का कुलसचिव अशोक कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। इस मौके पर डा. विनय तोमर और डा. विजय द्विवेदी आदि उपस्थित रहे।

छात्रों की उपाधियों पर एक नजर

जीएलए विश्वविद्यालय से वर्ष 2025 में पीएचडी के 69, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 71, बीएससी ऑनर्स बायोटेक के 21, बीएससी ऑनर्स कैमिस्ट्री के 19, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स के 11, बीए ऑनर्स अंग्रेजी के 23, बीबीए के 215, बीबीए ऑनर्स 147, बीबीए फैमिली बिजनेस 24, बीकॉम ऑनर्स ग्लोबल एकाउंटिंग 10, बीकॉम ऑनर्स 59, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी 24, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग 39, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 32, इलेक्ट्रॉनिक्स 5, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 41, एमई ऑटोमोबाइल एवं मेकाट्रॉनिक्स 2, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजी. 23, ईसी सीएस 34 एवं वीएलएसआई 9, कम्प्यूटर साइंस के 1138, बीटेक ऑनर्स सीएस 28, सीएस एआईएमएल 153, सीएस सीसीवी 25, सीएस डीए 34, सीएस सीएसएफ 24, सीएस आइआइओटी 7, बीसीए 476 एवं ऑनर्स 37, बीफार्म 77, बीएड 20, बीए एलएलबी ऑनर्स 42, बीकॉम एलएलबी ऑनर्स 12, एमएससी एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी एवं जीपीबी 3, एमएससी बायोटेक 10, माइक्रो एंड इम्यूनोलॉजी 5, एमएससी कैमिस्ट्री 11, गणित 4, फिजिक्स 3, एमटेक सीई स्ट्रक्चरल एवं ट्रांसपोर्टेशन 4, एमटेक सीएस 7, ईई 2, ईसी 2, एमटेक एमई प्रोडक्शन 3, एमबीए 604, एमबीए-बीए 25, ऑनर्स 30, एफएमबी 33, इंटेग्रेटेड 8, एलएससीएम 27, एमसीए 240, एमफार्म फामाकोलॉजी, फार्मास्युटिक्स 25, एलएलएम बीएफआईएल एवं सीडीपीएल के 14 विद्यार्थियों की उपाधि अनुमोदित की गई हैं। इसके अलावा डिप्लोमा कैमिकल के 12, डिप्लोमा सिविल इंजी. के 29, डिप्लोमा सीएस के 79, डिप्लोमा ईई 68, डिप्लोमा ईसी के 15, डिप्लोमा एमई के 116, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के 7 तथा डिप्लोमा इन फामेर्सी के 45 विद्यार्थियों को डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे।

प्रेस नोट गली मोहल्ला क्रिकेट लीग (GMCL) के लॉन्च में दिल्ली के युवाओं ने जबरदस्त हिस्सा लिया

दिल्ली, 2 दिसंबर, 2025: दिल्ली में गली मोहल्ला क्रिकेट लीग (ऋट्टउछ) के लॉन्च को युवाओं से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला, जिससे जी ऍ¨ ¨ सी एल सीजन 1 (2025झ 2026) की अच्छी शुरूआत हुई। कोच एग्ज़िबिशन मैचों में 16 टीमें थीं, हर टीम में 8 खिलाड़ी थे, और 29 और 30 नवंबर 2025 को दिल्ली के रामजस क्रिकेट ग्राउंड में हुए 15 प्लेऑफ-फॉर्मेट मैचों में हिस्सा लिया। इस मौके पर, बाबा इंदर प्रीत सिंह ने कहा, ह्लजो खिलाड़ी पहले टेनिस-बॉल बॉक्स क्रिकेट को एक हॉबी के तौर पर देखते थे, वे अब भारत और इंटरनेशनल लेवल पर इसके पोटेंशियल के बारे में जानने के बाद सीरियस हो रहे हैं। जी ऍ¨ ¨ सी एल न सिर्फ. भारत में बल्कि ग्लोबल लेवल पर युवाओं के लिए सबसे बड़ा ग्रासरूट प्लेटफॉर्म बनकर उभर रहा है। इन दो दिनों में मिले पार्टिसिपेशन और पॉज़िटिव फीडबैक ने इसे एक नेशनल मूवमेंट के तौर पर बढ़ावा दिया है ह्व जी ऍ¨ ¨ सी एल को फेज 1 के तहत पांच देशों—मीना रीजन, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया और नेपाल—के साथ-साथ पांच भारतीय राज्यों—दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। पार्टिसिपेंट्स ने इस इवेंट को लेकर अपना उत्साह दिखाया और बताया कि कैसे टेनिस बॉल बॉक्स क्रिकेट उन युवा लड़कों और लड़कियों के लिए एक बड़ा मौका बना रहा है जो प्रोफेशनल क्रिकेट करियर बनाना चाहते हैं। जी ऍ¨ ¨ बॉक्स क्रिकेट एसोसिएशन ने कोच एग्जीबिशन टूनार्मेंट से दो सबसे अच्छे बॉलर और दो सबसे अच्छे बैट्समैन चुनने के प्लान की भी घोषणा की। इन चुने हुए प्लेयर्स को 2026 की शुरूआत में होने वाले जी ऍ¨ ¨ सी एल के इंटरनेशनल एग्जीबिशन मैच में हिस्सा लेने का मौका दिया जाएगा। दो दिन के इवेंट का सफल कोऑर्डिनेशन और एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट टीम—गुरप्रीत कौर, एलेन, गौरव बाबर और राहुल ने किया, जिससे सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए एक आसान एक्सपीरियंस पक्का हुआ। फाइनल मैच हाइलाइट्स कोच एग्जीबिशन मैच (सेशन 1), 2025झ 2026 का फाइनल मैच इनके बीच खेला गया: ड्ट हिडन स्टार इंडिया यूट्यूब चैनल (कैप्टनः मिकी) ड्ट ईदगाह 11 (कैप्टनः राहुल राय पुरिया) हिडन स्टार इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, 8 ओवर में 72/6 रन बनाए। बल्ले से सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी थे: ड्ट सारथी: 34 रन (17 बॉल), 44, 65 ड्ट ललित: 16 रन (9 बॉल), 41, 62 ईदगाह 11 के लिए सबसे अच्छे गेंदबाज: ड्ट विकास राठी: 2 ओवर, 11 रन, 3 विकेट ड्ट सुमित मौर्य: 2 ओवर, 6 रन, 2 विकेट जवाब में, ईदगाह 11 ने 8 ओवर में 66/3 का स्कोर बनाया। टॉप स्कोरर: ड्ट राहुल रायपुरिया: 45 रन (31 बॉल), 43, 65 ड्ट वासु: 12 रन (6 बॉल), 62 हिडन स्टार इंडिया के टॉप बॉलर: ड्ट तैबू: 2 ओवर, 7 रन, 1 विकेट ड्ट मोनू कुमार: 2 ओवर, 19 रन, 1 विकेट फाइनल रिजल्ट: हिडन स्टार इंडिया यू टुब चैनल ने 6 रन से मैच जीता, और ऋट्टउछ सीजन 1 (2025झ2026) झ दिल्ली कोच एग्जीबिशन मैच का पहला विनर बना।

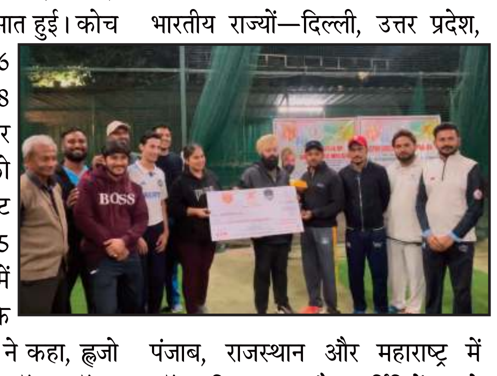

एसओजी टीम और बल्देव पुलिस की ईनामी शूटर से हुई मुठभेड़ : पुलिस की गोली से सुपारी किलर हुआ लंगड़ा

–शूटर ने सुपारी लेकर की थी वृद्ध की हत्या

मथुरा (जीएनएस)। थाना महावन क्षेत्र स्थित यमुना एक्सप्रेस-वे के पास एसओजी टीम और बल्देव पुलिस की फरार चल रहे ईनामी हत्यारोपी बदमाश से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से ईनामी बदमाश लंगड़ा हो गया। जानकारी के अनुसार एसएसपी श्लोक कुमार के निर्देशन में एसओजी प्रभारी राकेश कुमार पुलिस टीम के साथ फरार चल रहे ईनामी बदमाशों की तलाश में जुटे हुए थे। उसी दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना मिली एक वृद्ध की गोली मारकर हत्या करने के बाद फरार चल रहा सुपारी किलर, किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में यमुना एक्सप्रेस-वे के माइल स्टोन 140 के पास होकर जाने वाला है। सूचना मिलते ही एसओजी प्रभारी राकेश कुमार ने थाना प्रभारी बल्देव रंजना सचान को भी मौके पर बुला लिया। इसके बाद एसओजी प्रभारी राकेश कुमार और थाना प्रभारी बल्देव रंजना सचान ने फरार चल रहे 25 हजार के ईनामी सुपारी किलर को घेर लिया। पुलिस की घेराबंदी तोड़ने के लिए ईनामी बदमाश ने फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने जबावी कार्रवाई की तो 25 हजार के ईनामी बदमाश पवन उर्फ यशवीर उर्फ बंदर पुत्र पूरन सिंह निवासी बटपुरा थाना सहपाऊ जिला हाथरस के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार करने के बाद उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के कब्जे से बिना नंबर की बुलेरो पिकअप और एक तमंचा तथा कारतूस बरामद किए हैं। बताते चलें कि विगत 30 जुलाई को पकड़े गए ईनामी बदमाश को मृतक रघुवीर सिंह के पुत्र विनोद कुमार ने पिता की हत्या करने के लिए सुपारी दी थी। इसके बाद वृद्ध उदयवीर को बीमार होने पर उसका पुत्र विनोद दवा दिलाने के लिए बाइक पर लेकर जा रहा था। उसी दौरान वृद्ध के पुत्र की योजना के अनुसार पकड़े गए ईनामी बदमाश ने वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने पूर्व में मृतक के पुत्र रघुवीर सिंह, विनोद और पुत्री प्रीति को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। पुलिस ने पकड़े गए ईनामी बदमाश के खिलाफ कार्रवाई करके जेल भेज दिया है।

सुरो के सरताज ने महफिल सजाई हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव में

गुलदास्तां कार्यक्रम से भाव विभोर हुए दर्शक।

लखनऊ – 2 दिसंबर 2025: स्मृति उपवन में आयोजित माँ गायत्री जन सेवा संस्थान एवं नीशू वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव की सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ मुख्य अतिथि अध्यक्ष केयर एजुकेशनल ट्रस्ट डॉ सीमा यादव आयोजक अरुण प्रताप सिंह,गुंजन वर्मा, रनवीर सिंह एवं हेमू चौरसिया ने दीप प्रज्वलित कर किया। हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव में "सुरो के सरताज" का कार्यक्रम में कलाकारों ने सांस्कृतिक मंच से सुरो की आवाज बिखेर कर श्रोताओं और दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। सुरों के सरताज में देवेंद्र मैंगी ने दिल के टुकड़े-टुकड़े करके.... हिमांशु ने जन्म जन्म... नजर के सामने... सत्यम ने हर किसी को नहीं मिलता... पूनम, अनुराग, सीमा विरमानी ने आपके प्यार में हम... गीत गाकर श्रोताओं का मोहा मन। सीमा बिरमानी ने इस कार्यक्रम को संचालित किया। कार्यक्रम के अगले पड़ाव में सुनीता राय के संयोजन में एम एम एम ग्रुप सिंगर ने अपने-अपने हुनर दिखाएं।इस तरह से आशिकी... अनुराग श्रीवास्तव सूरज हुआ मध्यम.... राहुल कुछ ना कहो... संजय कुमार कह दूं तुम्हें... सुनील एवं शालू की जुगलबंदी से श्रोताओं को आकर्षित किया।कार्यक्रम के अंत में कल्याणी फाउंडेशन एवं केयर एजुकेशन एकेडमी द्वारा "गुलदास्तां" प्रस्तुत किया गया। संस्था की संयुक्त सचिव विमला द्विवेदी ने कहा दिव्यांग बच्चों को सही दिशा देना,आत्मविश्वास पैदा करना, उनके स्वाभिमान को बढ़ाना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। दिव्यांग बच्चों ने जिसमें विवेक, सोनिया सक्सेना, वेदांतिका श्रीवास्तव एवं शाश्वती चटर्जी ने प्रस्तुति दी। इस दौरान महोत्सव समिति के मोनालिसा, रोली जयसवाल व मनोज सिंह चौहान,रोली सिंह उपस्थित रहे। मंच का संचालन प्रदीप शुक्ला सहसंचालक विजय ने किया।

आर्यन प्रजापति का जबरदस्त मेकओवर- नए अंदाज में

यूपी। अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और एक्सप्रेसिव एक्टिंग के लिए मशहूर आर्यन प्रजापति, जो ह्यहप्पू की उलटन पलटनह्ल में ऋतिक का किरदार निभा रहे हैं, ने हाल ही में दर्शकों को अपने बिल्कुल नए अवतार से चौंका दिया। शो के नए बेटिंग-थीम्ड ट्रैक के लिए पहली बार आर्यन को पूरी तरह बदला हुआ लुक अपनाना पड़ा, जिसमें उन्हें खुद को बचाने के लिए एक अलग पहचान में दिखाया गया है। आर्यन ने इस चुनौती को बड़ी उत्सुकता और आत्मविश्वास के साथ स्वीकार किया। उनका यह मेकओवर कहानी में नया ट्विस्ट लाता है और बतौर कलाकार उनकी बढ़ती वर्सेटिलिटी भी दिखाता है।

अपने इस बदलाव के बारे में आर्यन प्रजापति उर्फ ऋतिक ने कहा, ह्यह्यपहली बार मुझे पूरी तरह से एक अलग लुक में आना पड़ा, और सच कहूं तो यह एक साथ रोमांचक और अजीब दोनों था। इस कहानी में ऋतिक को अपनी पहचान छिपानी थी, इसलिए मुझे बिल्कुल नया अवतार लेना पड़ा। जब मैंने मेकअप के बाद खुद को आईने में देखा, तो यकीन ही नहीं हुआ कि यह मैं हूं! इसकी तैयारी में काफी धीरज रखना पड़ा, क्योंकि हेयर और मेकअप सेट करने से लेकर एक्सप्रेशन्स और बॉडी लैंग्वेज बदलने तक, ताकि लुक नैचुरल लगे। मैंने जारा वारसी और सोनल पंवार दीदी से भी मदद ली और देखा कि लड़कियां कैसे बैठती, बात करती और रिएक्ट करती हैं, ताकि परफॉर्मेंस मजेदार भी रहे और असली भी, बिलकुल ऋतिक की तरह। यह चुनौतीपूर्ण था, लेकिन मजा बहुत आया क्योंकि इससे मुझे अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आने का मौका मिलाह्लह्ल यहां बता दें कि ह्यहप्पू की उलटन पलटनह्य सोमवार से शुक्रवार रात दस बजे एण्डटीवी पर प्रसारित है।

कलर्स के शो 'मन्नत हर खुशी पाने की' में सपनों की शादी बदल गई मन्नत के बुरे सपने में

हर लड़की अपनी शादी का सपना उम्र भर संजोकर रखती है, लेकिन क्या हो जब उसी सपने की बुनियाद हिला दे कोई ऐसा, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होड्ड खुद उसकी माँ? मन्नत की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बनने जा रहा उसका शादी का दिन अचानक दिल टूटने के कगार पर पहुँच जाता है। कलर्स का शो ह्यमन्नत हर खुशी पाने कीह्ल इस बड़े दिन को पूरी तरह उलट देता है, जहाँ बरसों से इंतजार किया गया जश्न पल भर में शक, तकलीफ और भावनात्मक उथल-पुथल से भर जाता है। अंतिम क्षणों में, जब मन्नत और विक्रांत अपने भविष्य को एक-दूसरे के नाम करने वाले होते हैं, फेरे के दौरान आने वाला एक ट्विस्ट पूरे माहौल को हिला कर रख देता है। ऐश्वर्या एक सोची-समझी गलतफहमी पैदा करती है, जिससे विक्रांत ये समझ ही नहीं पाता कि किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं।

इसके बाद सब कुछ एक झटके में बदल जाता है। खुद को ठगा हुआ महसूस करते हुए, विक्रांत अपने दत्तक माता-पिता रॉनी और नीतू से रिश्ता तोड़ देता है। वह रॉनी को मजबूर कर देता है कि वे अपनी संपत्ति विशाखा के नाम कर दें, और इसी के साथ रॉनी और नीतू को एक ही रात में सलूजा मैन्शन से बाहर निकलना पड़ता है। इस उथल-पुथल के बीच, मन्नत अपना पक्ष साफ कर देती है—वह रॉनी और नीतू के साथ खड़ी रहती है, ठीक उसी वक्त जब उनके पास सब कुछ छिन जाता है। अब सवाल ये है कि क्या मन्नत और विक्रांत का रिश्ता इस बड़े झटके के बाद भी कायम रह पाएगा?

देखिए ह्यमन्नत हर खुशी पाने कीह्ल रोजाना, सोमवार से रविवार, शाम 7:30 बजे, सिर्फ कलर्स पर

जियोहॉटस्टार की 'मिसेज देशपांडे' का ट्रेलर रिलीज, प्रीमियर 19 दिसंबर को

मुंबई, झ भूली-सी सूरत, आँखों में मस्तीड्ड लेकिन इस बार, उसी मुस्कान के पीछे छुपी है चुप्पी जो डर पैदा करती है। आज जियोहॉटस्टार ने अपनी नई सीरीज ह्यमिसेज देशपांडेह्ल का रोमांचक ट्रेलर लॉन्च किया। 6 एपिसोड की यह साइकोलॉजिकल थ्रिलर अप्लॉज एंटरटेनमेंट और कुकुनूर मूवीज द्वारा निर्मित है और इसका प्रीमियर 19 दिसंबर 2025 को होगा। इस सीरीज में माधुरी दीक्षित अपने ग्लैमरस और परिचित ऑन-स्क्रीन व्यक्तित्व से पूरी तरह अलग नजर आती हैं — एक सादा, खामोश और डराने वाली महिला, जिसकी मुस्कान और उसकी चुप्पी दोनों असहज कर देने वाली हैं। उनका यह परफॉर्मेंस इतना बारीक, अस्थिर और गहरा है कि दर्शक उन्हें इस रूप में पहले कभी नहीं देख पाए होंगे। तनाव, रहस्य और भावनाओं के मेल वाली यह सीरीज जियोहॉटस्टार की साल के अंत की सबसे प्रभावशाली रिलीज बनने की ओर बढ़ रही है वह कहानी जो खत्म होने के बाद भी दिमाग में चलती रहती है। मुंबई में दहशत फैल गई है शहर एक कॉपीकैट किलर की वजह से दहला हुआ है, जो पुराने सीरियल मर्डर पैटर्न को फिर से दोहरा रहा है। पुलिस के पास सुराग कम हैं और डर ज्यादा। और सबसे उलझन भरी बात असली किलर पहले से जेल में है। एक साधारण-सी दिखने वाली महिला, सबकी नजर में सामान्यड्ड लेकिन भीतर कहीं बहुत गहरा अंधेरा छिपाए हुए है। जैसे-जैसे पुराने राज, धोखे और दबी हुई सच्चाइयाँ सामने आती हैं, तनाव अपनी चरम स्थिति तक पहुँचता है क्योंकि कॉपीकैट को पकड़ने के लिएड्ड पुलिस को पहले असली किलर को समझना होगा। फ्रेंच थ्रिलर ला मांट से रूपांतरित और नागेश कुकुनूर द्वारा निर्देशित इस सीरीज में सिद्धार्थ चांदेकर, प्रियांशु चट्टर्जी और अन्य उत्कृष्ट कलाकारों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अप्लॉज एंटरटेनमेंट द्वारा कुकुनूर मूवीज के सहयोग से निर्मित मिसेज देशपांडे पहचान, मनोवैज्ञानिक नियंत्रण और उस महिला की भयावह शक्ति की कहानी है जो कम बोलती है, लेकिन हर बात उजागर कर देती है। माधुरी दीक्षित कहती हैं, ह्लमिसेज देशपांडे एक ऐसी महिला की खामोश ताकत की यात्रा है, जो बाहर से बिल्कुल साधारण दिखती है लेकिन उसके भीतर एक खतरनाक दिमाग छिपा है। हर ठहराव, हर निगाह, हर चुप्पी का एक अर्थ है। इस संयमित और तीव्र किरदार को निभाना चुनौतीपूर्ण और रोमांचक दोनों था। मैं उत्साहित हूँ कि दर्शक इस किरदार को देखेंगे जो परतदार है, अप्रत्याशित है और अब तक मेरे निभाए गए सभी पात्रों से बिल्कुल अलग है ह्व निर्देशक नागेश कुकुनूर जोड़ते हैं, ह्लट्रेलर दर्शकों को शो की असली टोन का संकेत देता है एक कैरेक्टर-ड्रिवन सीरियल किलर थ्रिलर। मिसेज देशपांडे में मैंने एक ऐसा यादगार ग्रे कैरेक्टर बनाने की कोशिश की है, जिसे देखकर दर्शक उसके पक्ष में खड़े होते हैं। और माधुरी दीक्षित ने इस किरदार को सिर्फ निभाया ही नहीं है, बल्कि उसे एक नए स्तर तक पहुंचा दिया है ह्व जियोस्टार के सीईओ आलोक जैन ने कहा, ह्लमिसेज देशपांडे आज के दर्शकों द्वारा खोजी जा रही बोल्ड और भावनात्मक रूप से सच्ची स्टोरीटेलिंग का प्रतिनिधित्व करती है। हमें शुरूआत से स्पष्ट था कि यह भूमिका केवल माधुरी दीक्षित ही निभा सकती हैं क्योंकि उद्देश्य उनके परिचित ग्लैमरस पसोर्ना को पूरी तरह तोड़ना था। यहाँ वह एक कठोर, बिना मेकअप वाले और बेहद शांत लेकिन डरावनी उपस्थिति के साथ दिखाई देती हैं। यह दर्शक पहली बार उनके कला का यह रूप देखेंगे ह्व उन्होंने आगे कहा, ह्लयह सीरीज इसलिए अलग और प्रभावशाली है क्योंकि इसने क्राइम जॉनर को सटीकता, मनोवैज्ञानिक गहराई और एक भयावह भावनात्मक परत के साथ आगे बढ़ाया है। यह स्ट्रीमिंग दर्शकों के लिए प्रीमियम, महिला-प्रधान क्राइम आईपी तैयार करने की हमारी रणनीतिक दिशा को भी दशार्ता है। जियोहॉटस्टार पर हमारा उद्देश्य ऐसी कहानियां लाना है जो सोचने पर मजबूर करें और देखने के बाद भी मन में बनी रहें और मिसेज देशपांडे बिल्कुल वैसी ही कहानी है ह्व अप्लॉज एंटरटेनमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर समीर नायर ने कहा, ह्लजियोहॉटस्टार और अप्लॉज के बीच क्रिएटिव साझेदारी हर नई कहानी के साथ और मजबूत हुई है। इस वर्ष की हमारी हैट्रिक क्रिमिनल जस्टिस, सर्च: द नैना मर्डर केस, और अब मिसेज देशपांडे हमारे साझा उद्देश्य को दशार्ती है: ऐसी प्रीमियम स्टोरीटेलिंग प्रस्तुत करना जिसमें स्केल हो, भावना हो और एक स्पष्ट रचनात्मक इरादा हो। नागेश कुकुनूर के उत्कृष्ट निर्देशन और माधुरी दीक्षित के अब तक के सबसे अप्रत्याशित किरदार के साथ, मिसेज देशपांडे एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो हर मोड़ पर दर्शकों की अपेक्षाओं को चुनौती देती है ह्व क्या वह कॉपीकैट को पकड़ने में मदद कर रही हैड्ड या अपने ही छिपे एजेंडा के लिए खेल कर रही है? देखिए मिसेज देशपांडे 19 दिसंबर से, केवल जियोहॉटस्टार पर।